देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित

www.page3news.in

नगर संस्करण वर्ष 18 अंक: 186 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

विचार-प्रवाह...
जंग का एलान

पेज थ्री

देहरादून, मंगलवार, 31 अक्टूबर 2023

मौसम अधिकतम 27.0° न्यूनतम 17.0°

66023.69

2 गाजा को रौंद रहा इजरायल

7 पंड्या अगले 3 मैच से भी हुए बाहर

15 साल से पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर मिलेगी सब्सिडी

धामी कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों को भत्ता समेत 15 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

संवाददाता

देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक हुई। देहरादून स्थित सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में औद्योगिक विकास, महिला सशक्तीकरण, वन, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन और शहरी विकास से संबंधित फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में वर्षा जल संरक्षण के लिए हजारों डैम, एक अक्टूबर, 2005 तक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए कार्मिकों को भी पुरानी पेंशन का विकल्प सहित कई अहम विधेयक पर मुहर लगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है कि 15 साल से पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर उत्तरखंड सरकार सब्सिडी देगी।

कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियों पर टैक्स छूट का निर्णय लिया गया है। सूत्रों की बात मानें तो पर्यावरण के मद्देनजर और प्रदूषण पर रोक लगाने को यह फैसला लिया गया है। यही नहीं, दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया गया है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके तहत 2005 से पहले विज्ञप्ति वाले कर्मियों को पुरानी पेंशन मिल सकेगी। कैबिनेट में फैसला लिया गयाा है कि उत्तराखंड में गाड़– गदेरों पर चेकडैम बनाने के लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा। इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में बरसाती पानी को रोकने के लिए चेकडैम बनाने पर ठोस प्लान बनाकर कार्य किया जाएगा।

सीएम धामी सरकार ने उत्तराखंड में वन पंचायतों में जड़ी बूटी उत्पादन को भी मंजूरी दी है। 10 साल के भीतर 5 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में उत्पादन करने का लक्ष्य तय गया है। 35 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उत्तराखंड सरकार 2400 सलाना वर्दी भत्ता भी देगी।

कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि घरों में सोलर हीटर लगाने पर सरकार की ओर से भवन स्वामी को सब्सिडी भी देगी। इसके अलावा, मुनिकीरेती को पालिका, कैंपटी फाल व गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाने का भी फैसला लिया गया है।

उत्तराखंड में पुराने उद्योगों के विस्तार पर सब्सिडी देने का भी फैसला लिया गया है। सीएम धामी सरकार ने आठवीं के बाद आईटीआई करने पर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके लिए छात्रों को हिंदी का पेपर देना होगा।

कैबिनेट बैठक से पहले विधायक सरवत करीम के निधन पर मौन

सचिवालय में सोमवार को कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन पर कैबिनेट द्वारा दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद बैठक की कार्रवाई शुरू की गई। मंगलौर से बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी का सोमवार सुबह दिल्ली के एक अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। विधायक के निधन की सूचना मिलते ही बसपा कार्यकर्ताओं और कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई। वह दो बार के मंगलौर के विधायक रहे।

राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी

मुख्यमंत्री धामी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए कहा कि देश की एकता और अखंडता की रक्षा में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एकीकृत भारत के निर्माण में सरदार पटेल की कूटनीति व दूरदर्शिता का महत्वपूर्ण योगदान है। युवा पीढ़ी को सरदार पटेल के आदर्शों से प्रेरणा लेकर देश के सर्वांगीण विकास के लिए अपना योगदान देना होगा। आज का दिन हमें अपने को राष्ट्र की सेवा के लिये समर्पित करने की भी प्रेरणा देता है।

संक्षिप्त समाचार

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को नहीं दी जमानत

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया को झटका देते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता की जमानत याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को इस मामले को 6 से 8 महीने के अंदर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने टिप्पणी की कि यदि केस की सुनवाई धीमी गति से होती है तो सिसोदिया तीन महीने के बाद फिर से बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं।

हम गठबंधनों पर कुछ नहीं कर सकते

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। इंडिया गठबंधन के नाम पर सवाल उठाने वाली याचिका को लेकर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में चुनाव आयोग ने बताया है कि वह राजनीतिक गठबंधनों को रेगुलेट नहीं कर सकते। उन्हें संविधान के तहत रेगुलेटरी संस्था के रूप में मान्यता नहीं है।

भूमाफिया ने आईएएस–आईपीएस समेत हाई प्रोफाइल को ठगा

जमीन खरीदने वालों में मौजूदा आईएएस, आईपीएस समेत हाई प्रोफाइल शामिल

संवाददाता

देहरादून। विकासनगर नगर पालिका परिषद से आठ किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर स्थित पौंधा में भूमाफिया ने प्रदेश के कई वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस के साथ ठगी करते हुए उन्हें अवैध प्लाट बेच दिये। यह जमीन हरिजन की है और इसके लिए कलक्टर से कोई अनुमति नहीं ली गयी। 300 बीघा जमीन में दिशा–एक और दिशा–दो के नाम से चल रहे इस प्रोजेक्ट में सरकार को भी स्टाम्प ड्यूटी की भारी चपत लगी है। गढ़वाल कमिश्नर ने जिलाधिकारी को इस मामले की जांच के आदेश दिये थे, लेकिन इसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल हैं तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने इस मामले का खुलासा किया है। उन्होंने आरटीआई के जरिए इस भूमि संबंधी दस्तावेज मांगे। मिली जानकारी के अनुसार पौंधा में दिशा फारेस्ट के नाम से इंद्र सिंह बिष्ट, एस.सी माथुर समेत एक गिरोह ने संगठित तरीके से 150–150 बीघा भूमि में दो प्रोजेक्ट शुरू किये हैं। इन्हें दिशा–वन और दिशा–टू नाम दिया गया है। इस भूमि पर प्रदेश के आईएएस और आईपीएस अफसरों की कालोनी बनाई जा रही है।

एडवोकेट विकेश नेगी के अनुसार यह कृषि भूमि है। यह पहले हरिजन के नाम थी और बाद में इसे सरकार के अधीन रही। अब इसमें निजी कालोनाइजर शामिल हो गया। उनके मुताबिक इस जमीन पर लगभग डेढ़ हजार पेड़ थे। इन पेड़ों को बिना अनुमति काट डाला गया। आरटीआई से मिले दस्तावेजों के मुताबिक यहां प्लाट खरीदने वालों में उत्तराखंड के कई मौजूदा आईएएस, आईपीएस, पूर्व आईएएस, समेत कई अन्य नौकरशाह और हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं। जिनके साथ जमीन खरीद के नाम पर यह ठगी हुई है।

भूमि की जांच बैंक ने भी की

भूमि की जांच बैंक ने भी की। बैंक की ओर से जांच रिपोर्ट में कहा गया कि पांच सेल डीड की जांच में पाया गया कि इसमें उत्तर प्रदेश भूमि जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 157 ए का भी उल्लंघन किया गया है। इस जमीन को खरीदने–बेचने के लिए कलक्टर की अनुमति चाहिए जो कि नहीं ली गयी।

शिक्षकों ने किया लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान

संवाददाता

देहरादून। सरकार पर शिक्षकों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए राजकीय शिक्षक संघ ने सोमवार को आरपार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। यदि सरकार ने लंबित मांगों पर ठोस कार्यवाही न की तो अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का शिक्षक बहिष्कार करेंगे। इसके साथ ही शिक्षक विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल न होंगे और न ही ऑनलाइन हाजिरी भरेंगे। साथ ही प्रभारी के रूप में प्रधानाचार्य का काम देख रहे शिक्षक भी अपनी जिम्मेदारी को छोड़ देंगे। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। अगले सोमवार छह नवंबर को शिक्षा निदेशालय की तालाबंदी भी की जाएगी।

सोमवार को सोमवार को ननूरखेड़ा स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय परिसर में धरना–प्रदर्शन के दौरान संघ पदाधिकारियों ने आंदोलन के अगले चरण की घोषणा की। 27 सितंबर से शुरू हुए आंदोलन के पांचवे चरण में शिक्षक पदाधिकारी आज सुबह 10 बजे से निदेशालय के मुख्य द्वार के बाहर धरने पर बैठे। सरकार पर शिक्षकों की मांगों के प्रति लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चार अगस्त को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में 35 मांगों पर चर्चा की गई थी। करीब करीब सब पर कार्यवाही का आश्वासन भी दिया गया। लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

शिक्षक आंदोलन

- सरकार पर शिक्षकों ने लगया उपेक्षा का आरोप

इसलिए नाराज हैं शिक्षक

शिक्षकों की नाराजगी की भी कई वजहें हैं। पिछले कई सालों से एलटी, हेडमास्टर और प्रिंसीपल के प्रमोशन की प्रक्रिया लटकी है। शिक्षक वर्षों से एक ही पद पर काम करते हुए रिटायर हो रहे हैं। अब तक सरकार इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए हैं।

Are you Planning to make a Website or already have ?
If yes, then we are here to serve you
What we do
Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.
Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS
Search Engine Optimisation
A-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.
Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. | Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in

उत्तरी और सेंट्रल गाजा के अंदर घुसी इजरायली सेना

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

गाजा पट्टी। इजरायल और हमास के बीच युद्ध का 24वां दिन है, दोनों तरफ से हुई हजारों मौतों हुई हैं। इस बीच इजरायली सैनिक सोमवार को उत्तरी और मध्य गाजा में अंदर तक घुस गए और जमीनी हमले किए। दरअसल, संयुक्त राष्ट्र और चिकित्सा कर्मचारियों ने इजरायल को चेतावनी दी थी कि उसकी तरफ से हवाई हमले उन अस्पतालों के पास हो रहे हैं जहां हजारों फलस्तीनियों ने हजारों घायलों के साथ आश्रय मांगा है। सेंट्रल गाजा में एक इजरायली टैंक और बुलडोजर को क्षेत्र के मुख्य उत्तर–दक्षिण हाईवे को बाधित करते हुए दिखाया गया है। इस हाईवे का इस्तेमाल फलस्तीन के आम नागरिक हमलों से बचने के लिए कर रहे थे।

सेना की वर्तमान तैनाती पर टिप्पणी नहीं करेंगेः इजरायल

इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा, हमने अपने हमलों को आगे बढ़ाया है, लेकिन सेना की वर्तमान तैनाती पर टिप्पणी नहीं करेंगे। वहीं, इजरायल ने गाजा शहर के दोनों किनारों और उत्तरी गाजा के आसपास के इलाकों में सेना की तैनाती की है।